RAJYA SABHA

Thursday, the 21 st *August, 2003/30 Sravana,* 1925 *(Saka)*

The House met at eleven of the Clock,
MR. CHAIRMAN in the Chair

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Indians in Pakistani Jails

*401. SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY:†
SHRI AMAR SINGH:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of Indian civil prisones and fishermen in Pakistani jails, at present;

(b) the number of Pakistani prisoners and fishermen in Indian jails, at present;

(c) the steps being taken to get them released from the respective countries;

(d) whether Pakistan has given any assurance in this regard; and

(e) if so the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH): (a) to (e) A Statement is placed on the Table of the House.

Statement

As per available information following numbers of Indian and Pakistani civilian prisoners and fishermen are detained in each other's jails.

	Indian Prisoners in Pakistan	Pakistani Prisoners in India
Civilians	868	338
Fishermen	319	093

Prisoners are released in accordance with established procedure, involving consular access and verification of nationality by the concerned

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Ravula Chandra Sekar Reddy.

Government, after their jail sentence is over. Government have consistently taken up the matter of release of Indian civilian prisoners and fishermen detained in Pakistan. As a result, Pakistan provided consular access to 110 Indian civilian prisoners during 2002-03. Out of these, 20 prisoners were repatriated on 18.5.2003. Nationality of another 80 prisoners has been confirmed to Government of Pakistan who have been requested to fix an early date for their release. Response from Pakistan is awaited. Nationality verification of remaining 10 civilan prisoners is under process. Government have also confirmed the nationality of 319 Indian fishermen detained in Pakistan. A 6 member fishermen association's delegation from Gujarat is currently in Pakistan for carrying out the repairs of boats to facilitate the early repatriation of detained fishermen.

Government provided consular access to 87 Pakistani civilian prisoners and 93 fishermen during the year 2002-03. Of these, 6 Pakistani civilian prisoners, whose nationality was confirmed, were released on 25.6.2003. A Pakistani fishermen association's delegation is scheduled to visit Indian shortly to carry out repairs of boats to facilitate repatriation of detained Pakistani fishermen.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, there are about 868 civilians and 319 poor fishermen in the Pakistani jails. I would like to know from the hon. Minister the details of Pakistani prisoners in Indian jails for more than ten years, the directions of the Supreme Court given to the Indian Government in this regard, and also, the position with regard to Indian prisoners lodged in Pakistani jails.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Sir, as regards the question of Indian prisoners in Pakistani jails, they broadly fall under four categories: detained fishermen, civilian prisoners, prisoners of war, and others. In the last category are persons whom Pakistan has wrongly accused of spying and such activities, and sometimes, classified them as security prisoners.

The protocol on consular access signed between the two countries in 1982 covers the categories of prisoners who are not apprehended for political or security reasons or offences. There is a set procedure for release of detained fishermen and civilians. Release of those in the fourth category is normally sought through exchanges.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, he has not covered my question. My question was with regard to the direction given by the Supreme Court to the Indian Government, and the joint steps proposed to be taken to clear all the hurdles for getting the civilian prisoners and fishermen released from the jails in the respective countries.

SHRI DIGVIJAY SINGH: Sir, as far as the direction of the Supreme Court is concerned, I wish to say that there is no such direction from the Supreme Court; there is a notice from the Supreme Court and we are examining it.

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY: Sir, my second supplementary is: recently, our Parliamentarians visited Pakistan, and they favoured uninterrupted Indo-Pak dialogue covering all the issues. The MP's delegation felt that in Pakistan, there is a strong desire for peace and cooperation with India. What is the declared policy of Pakistan Government in regard to Indians in Pakistani jails?

SHRI DIGVIJAY SINGH: Sir, as far as the media and Parliamentarians delegation is concerned, it is a people to people contact, and we are all happy that the Parliamentarians of this country have been well-received by the people of Pakistan. As for the hon. Member's suggestion about the desire of the people of Pakistan for peace and cooperation, we are all concerned about it, and we appreciate that.

श्री अमर सिंह: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जब दिनांक 1-12-1999 को प्रश्न संख्या 473 को प्रश्न संख्या 473 पूछा गया था तो उस सरकार ने एक सूची भी सदन को बताई थी, तो वर्ष 1971 से जो बंदी पाकिसातन की जेलों में पड़े हुए हैं उनको छुड़ाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है? दूसरा, अगर वे इन्हें प्रिजनर्स आफ वार नहीं मानते हैं, कोई दूसरा क्राइम मानते हैं इन सैन्य अधिकारियों का या इन लोगों का, तो इनके लिए आपने क्या कोई स्ट्रेटजी बनाई है कि कैसे इनको उनकी कैद से रिहाई दिलाई जाए?

श्री दिग्विजय सिंह: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा है क्योंकि इस सावल से पूरे देश की चिंता हमेशा बनी रहती है। यह बात सही है कि हमारे कुछ प्रिजनर्स आफर वार, जिनको हम मानते हैं, वे पाकिस्तान में हैं और इसके बारे में हमने हमेशा पाकिस्तान को याद दिलाया है। वर्ष 1983 में पहली बार हमारे और उनके बीच एक करार हुआ था और उस करार के मुताबिक पाकिस्तान में दो जगहों, एक मुल्तान और दूसरा कराची और दिन्दुस्तान में दो जगहों, एक जयपुर और दूसरा राजकोट, को चिन्हित किया गया था, जहां कौंसलर, जिसको हम कहते हैं

कि वे एक दूसरे से जानकारी लेने और देने का काम करते हैं, वे रखें। तो वहां पर यह काम हो रहा है। जहां तक प्रिजनर्स आफ वार का है, जब मुशर्रफ साहब स्वयं राष्ट्रपति की हैसियत से हिन्दुस्तान आए थे तो उस समय भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने उनके सामने इस सवाल को रखा था और उन्होंने यह विश्वास और भरोसा दिलाया था कि हम किसी भी प्रिजनर आफ वार को अपने यहां नहीं रखेंगे, लेकिन भारत सरकार आज भी यह मानती है कि हमारे प्रिजनर्स आफ वार, जिनको हमने चिन्हित किया है, जिसमें 54 का नाम बताया है, वे 54 लोग आज भी वहां पर मौजूद हैं और इनको हमें वापस देना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि भारत के इस प्रस्ताव को पाकिस्तान के राष्ट्रपति और पाकिस्तान की सरकार ने अब तक स्वीकार करने से इंकार किया है और कहा है कि हमारे पास किसी भी तरह का कोई भी प्रिजनर आफ वार मौजूद नहीं है। आज भी जो उनके रिश्तेदार हैं वे चाहते हैं कि हमें वहां जाने दिया जाए और उन्होंने तीन शर्तें रखी हैं कि अगर इन तीन शर्तों के साथ हमें पाकिस्तान जाने की इजाजत दी जाए तो हम अपने प्रिजनर्स को वहां पर चिन्हित कर सकते हैं। जो तीन शर्तें उन्होंने रखी है, उनमें उन्होंने कहा है कि हमें सारी जेलों में जाने की इजाजत मिले, हमें पूरे रिकार्ड देखने को इजाजत मिले और पाकिस्तान तथा हिन्दुस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन से जुड़े हुए लोगों को हमारे साथ जाने की इजाजत दी जाए। दुर्भाग्य से यह प्रस्ताव, जो उनके रिश्तेदारों का प्रस्ताव है, वह पाकिस्तान की सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। लेकिन हम अभी भी अपनी तरफ से प्रयासरत हैं पाकिस्तान को यह समझाने में कि इन प्रिजनर्स आफ वार की भारत को वापस दिया जाए।

प्रो.रामबख्श सिहं वर्मा: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मालूम करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो 319 भारतीय मछुआरे हैं, उनमें 314 की राष्ट्रीयता की पहचान कर ली गई है लेकिन शेष की अभी पहचान नहीं हुई है, उनकी स्थिति क्या है?

मेरे प्रश्न का "ख" भाग है कि ये जो मछुआरे या सिविलियन कैदी होते हैं, इस देश से उस देश वापिस जाने के लिए और उस देश से इस देश में वापिस आने के लिए इनकी इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भारत सरकार पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने पर विचार करेगी?

श्री दिग्विजय सिंह: सभापति महोदय, दुर्भाग्य से भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई समुद्री सीमा तय नहीं है, जिसको हम लोग मेरिटाइम बाउंड्री कहते हैं। इसको रेखांकित करने में हम लोग सफल नहीं हो पाए हैं। क्योंकि कोई सीमा तय नहीं है, सीमा की पहचान नहीं है, ऐसे में हमारे मछुआरे मछली की तलाश में बार बार पाकिस्तान की तरफ चले जाते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि पाकिस्तान में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपने बिल्कुल सही पूछा कि भारत सरकार उन लोगों को छुड़ाने की दिशा में क्या काम करती है? आपने स्वंय ही उत्तर दिया कि हमारे

मछुआरे, जिनकी संख्या सैकड़ों होती है, उन मछुआरों को छुड़ाने में हम हमेशा कामयाब होते हैं और अभी तत्काल काफी मछुआरों को वहां से छोड़ा गया है।

जहां तक आपके प्रश्न के "ख" भाग का सवाल है जिसमें आपने एक सुझाव यह दिया है कि क्या इस बारे में कोई ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का इरादा है जिससे इस काम में कुछ सहूलियत हो सके, इस बारे में मेरा कहना है कि आप जानते हैं कि हमारे रिश्ते सुधार की तरफ है। भारत-पाकिस्तान के लोगों की यह इच्छा है, सरकारों की यह इच्छा है कि हमारे संबंध सुधरें और जब हमारे संबंध सुधरेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई परेशानी हमारे सामने आएगी।

SHRI N. JOTHI: Sir, it is a routine affair for Rameshwaram fishermen to be taken away by the Sri Lankan Navy or by the Sri Lankan fishermen. It is happening daily. Daily twenty, thirty or fifty fishermen are taken away. Not even a single day goes without these people being caught by them. Whenever the question is raised, law and order problem arises in Tamil Nadu. Our Chief Minister has also written letters to various Offices or Ministries here. But it is going on like this. Neither the Coast Guard is taking any action in this regard nor the Ministry of External Affairs seems to be having any permanent solution of this issue. My question is: What are the concrete steps taken by the Government of India to prevent this kind of affairs? Will there be any agenda to take back Kachchathivu Island that has been wrongly given to Sri Lanka? It is very near Rameshwaram. They say that their coastal area territorial boundary extends up to that island. What is the permanent solution that the Government has got for this issue? It is a daily menace that is going on. Is the Ministry aware of this? We would like to know about this.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI YASHWANT SINHA): Sir, on the question of Indian fishermen straying across the international boundary into Sri Lankan waters, as far as that issue is concerned, we are in touch with the very friendly Government of Sri Lanka, and from time to time we make sure that through intervention of our High Commission in Sri Lanka these fishermen are released. But it is a fact, Sir, that often despite the clear demarcation of the international waters of the two countries, fishermen stray across into the Sri Lankan waters. We have advised the Government of Tamil Nadu; we have advised the fishermen's associations to be careful with regard to this so that these incidents do not arise, but even after this, as I said, whenever such a situation arises, when our fishermen are apprehended by the Sri

Lankan authorities, then, we immediately intervene. I personally know of many cases where our intervention has been effective and the fishermen have been released. I was, Sir, supposed to go to Sri Lanka on the 19th and 20th; I could not for other reasons. But, this was one of the issues that I had proposed to take up with them. Whenever we get an opportunity to apprise the Sri Lankan autorities of our concerns, we do so; we will continue to do so; we are trying to workout institutional arrangement with the Sri Lankan authorities. I would like to assure this House that in this matter, we have received the fullest co-operation of the Sri Lankan authorities, unlike in the case of Pakistan where such co-operation is not always forthcoming. In the case of Sri Lanka, such co-operation is always forthcoming.

As far as Kachchathivu Island is concerned, it has been repeatedly stated, decided, confirmed even by the Government of India that this Island falls in Sri Lankan waters, that we have no sovereign right over this. It is only a question of our fishermen getting some concession from the Sri Lankan Government so that they could, perhaps, dry their nets, etc. They can't fish in those waters around Kachchathivu Island, but some facilities, like drying of nets, etc., is something which is under negotiations.

SHRI LALIT SURI: Mr. Chairman, Sir, I would like to ask the hon. Minister whether the Government is aware that quite a good number of Indian prisoners languishing in Pakistan jails for a long period have become insane. Is there some mechanism, with the help of international forum, where we can find the physical and mental health of these prisoners?

SHRI DIGVIJAY SINGH. Mr. Chairman, Sir, I have already partially answered this question and the hon. Member had just raised this issue and if you permit me, I may repeat it for him also. Indian prisoners in Pakistani jails broadly fall in four categories, namely, detained fishermen, civilian prisoners, prisoners of war, and others. In the last category, a person whom Pakistan has wrongly accused of spying and such activities and sometimes classifies them as security prisoners. Number two, the protocol on Consulars Access signer between the two countries in 1982, covers the categories of prisoners who are not apprehended for political or security risks or offences. And, number three, there is a set procedure for release of detained fishermen and civilian prisoners. Release of those in fourth category is normally sought through action basis.

As far as international intervention for checking their mental assessment and other things are concerned, India firmly believe that issues between India and Pakistan can be resolved bilaterally and there is no need of third intervention.

*402. [The questioner (Shri Dwijendra Nath Sharmah) was absent. For answer vide page 28 infra].

सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का कारोबार

*403. **श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"**: †

श्री राम जेठमलानी:

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूचना प्रौद्यौगिकी उद्योग का कारोबार वर्ष 2006 तक 1,96,105 करोड़ रुपए तक होने की आशा है,

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या आकलन है,

(ग) क्या इस कारोबार में राज्य की भागीदारी का भी आकलन किया गया है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार व्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (घ) एक विवरण-पत्र राज्य सभा के पटले पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक उच्चतर विकास दर का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर गठित दसवीं पंचवर्षीय योजना कार्यकारी दल ने सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए वर्ष 2006-07 में 2,23,000 करोड़ रुपए के कारोबार का लक्ष्य रखा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†सभा में यह प्रश्न श्री राजीव रंजन सिंह ललन द्वारा पूछा गया।